डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 सितम्बर, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 सितम्बर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 08 | भोपाल | 16 सितम्बर, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

# मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की केंद्रीय मंत्री श्री शाह से भेंट

**प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ने से साँची दुग्ध संघ का होगा उन्नयन**

**प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया**

**राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हुआ त्रि-पक्षीय एमओयू**

**साँची ब्रांड और अधिक बेहतर बनेगा**

**भोपाल :** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सौजन्य भेंट कर प्रदेश के सहकारिता संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि गत दिवस राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन आगामी पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस समझौते से लगभग 11 हजार गांवों के पशुपालक और दुग्ध-उत्पाद किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इन 11 हजार गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन करेगी। डॉ. यादव ने अवगत कराया कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ने से साँची दुग्धसंघ का उन्नयन होगा। साँची ब्रांड को और बेहतर बनाया जायेगा।

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के बाद दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। प्रदेश में प्रतिदिन साढ़े पांच करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जहां देश में प्रति व्यक्ति 459 ग्राम दूध प्रतिदिन की उपलब्धता है वहीं मध्यप्रदेश में यह 644 ग्राम है। अगले पांच वर्ष में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने और किसानों एवं पशुपालकों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य होगा। प्रदेश के करीब चालीस हजार ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्तमान में 10 से 15 हजार ग्रामों में दुग्ध उत्पादन की स्थिति संतोषजनक है। शेष ग्रामों में विभिन्न उपायों से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देश में दुग्ध सहकारिता के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध विपणन, तकनीकी सलाह, दुग्ध प्रसंस्करण, पशु प्रजनन, पशुपालन से संबंधित आधुनिकतम तकनीकी परामर्श इत्यादि कार्य करती है। मध्यप्रदेश में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एकत्रीकरण की क्षमता को बढ़ाने व प्र-संस्करण एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा सहयोग दिए जाने पर सहमति दी गई।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने प्रदेश शासन के इस नवाचार की सराहना की और इस दिशा में पूरे प्रदेश में काम करने का सुझाव दिया। श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में केंद्र सरकार द्वारा से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से प्रदेश के दुग्ध-उत्पादक किसानों की संपन्नता के साथ खाद्य प्र-संस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के लिए न केवल कच्चे माल बल्कि उनके उत्पादो पर भी पूरी भागीदारी होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को मध्यप्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने के निर्णय के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

### त्रि-पक्षीय एमओयू के मुख्य बिन्दु

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मध्यप्रदेश पशुपालन और स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के बीच त्रि-पक्षीय समझौता हुआ।
- डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी कवरेज का विस्तार किया जायेगा।
- कृषक प्रशिक्षण एवं सहकारी डेयरी कवरेज में वृद्धि के लिये सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों, स्व-सहायता समूहों और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों(M-PACS) को शामिल करेंगे।
- दुग्ध संकलन, परिवहन और प्र-संस्करण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता सुधार करेंगे।
- मौजूदा बुनियादी ढाचे का इष्टतम उपयोग, संयंत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन और एण्ड-टू-एण्ड डिजिटलीकरण करेंगे।
- अन्य राज्यों में विपणन और विदेशों में निर्यात के लिये नीतिगत सुझाव सहित दूध और दुग्ध उत्पादों की बाजार में विपणन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण करेंगे।
- मानव संसाधनों की पद स्थापना एवं क्षमता निर्माण किया जायेगा। डेयरी सहकारी समितियों के लिये चुनाव प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जायेगा।
- ग्वालियर और जबलपुर का दुग्ध संघ का पुनरुत्थान एवं जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के पुनर्गठन और जबलुर संभाग के लिये पुनर्गठित जबलपुर दुग्ध संघ और शहडोल और रीवा संभाग के लिये नये रीवा-शहडोल दुग्ध संघ की स्थापना के लिए नीतिगत सुझाव संबंधी सहमति बनी।

## कृषकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति गठित

**भोपाल :** राज्य शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। यह समिति आईएफसी (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा संचालित एग्टेक बैक्ड कंसोर्टियम के सहयोग से कार्य करेगी। इस पहल से राज्य में एग्टेक इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का समावेश सुनिश्चित होगा। इस स्टीयरिंग कमेटी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

समिति में अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम,सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास, प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविालय, महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, संचालक कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि समिति के सदस्य एवं संचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे।

समिति एग्टेक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और आवश्यक संस्थाओं की सलाह लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एग्टेक कंपनियों, निवेशकों, और विभिन्न संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे मध्यप्रदेश में एग्टेक इकोसिस्टम को और सुदृढ़ किया जा सके। समिति अपने प्रतिवेदन और सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस कदम से एग्टेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में कृषि आधारित व्यापार को एक नई दिशा प्राप्त होगी।

# प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की करेंगे स्थापना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**सिंचाई परियोजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में समय पर पहुंचे**

**मुख्यमंत्री ने की सहकारिता विभाग और नर्मदा नियंत्रण मंडल के कार्यों की समीक्षा**

**भोपाल :** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने 4 करोड़ 27 लाख के लाभांश का चेक भेंट किया।

बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 ऑइल मिल की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद अंतर्गत नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंको को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए योजना तैयार करें।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के कार्यों और मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ की विभिन्न लेनदारियों के संबंध में बैठक में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि अपेक्स बैंक में राज्य शासन द्वारा 142 करोड़ रुपए की अंशपूंजी निवेशित की है। बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित कोर बैंकिग सोल्यूशन प्रणाली पर कार्यरत हैं। अपेक्स बैंक को 131.83 करोड़ का संचित लाभ हुआ है। अपेक्स बैंक द्वारा राज्य शासन को विगत 4 वर्ष में 12 करोड़ 10 लाख रुपए राशि का लाभांश दिया है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छे ढंग से कराए जा रहे हैं। बुरहानपुर और खरगोन में शक्कर कारखाने कार्य कर रहे हैं।

### नर्मदा नियंत्रण मंडल की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मंडल की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। परियोजनाओं की निविदा एवं स्वीकृति की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को सिंचाई परियोजनाओं से अधिक लाभ मिलेगा।

# प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों के लिए 7 नई कृषि परियोजनाओं को दी मंजूरी

- **कृषि क्षेत्र और किसानों को नई दिशा देने का संकल्प**
- **प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार**

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जीवन को क्रांतिकारी तरीके से बदलने के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपये की लागत वाली सात प्रमुख कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को किसानों के हित में लिये गये इस निर्णय के प्रति आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने किसानों के जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया युग शुरू होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि, "हमने सफल पायलट प्रोजेक्ट्स के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करेगा, जो किसानों की जिंदगी को नई तकनीकी ऊंचाइयों पर ले जाएगा।"

कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से पहला है डिजिटल कृषि मिशन, जो एआई, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा।

इसके अलावा, खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर 3,979 करोड़ रुपये की लागत से 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो 2047 तक जलवायु-संवेदनशील फसल विज्ञान को बढ़ावा देगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत कृषि शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 2,291 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार शामिल है।

पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये, बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए क्रमशः 1,115 करोड़ रुपये और 1,202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

# श्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया

**साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू है**

**कोई एक संस्था या इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं कर सकते इसके लिए इसके सभी स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर आकर साथ में काम करना होगा**

**राष्ट्रीय स्तर पर 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' बनाने और इसके साथ राज्यों को जोड़ने से साइबर अपराध के रोकथाम में मदद मिलेगी**

**5 साल में लगभग 5 हज़ार साइबर कमांडो होंगे तैयार**

**तीन नए आपराधिक कानूनों में देश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए सभी कानूनी इंतजाम किए गए हैं**

**दिल्ली।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया।गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) राष्ट्र को समर्पित किया और समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने 'Cyber Commandos' कार्यक्रम और Suspect Registry का भी उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री ने I4C के नए लोगो, विजन और मिशन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार, केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहन, निदेशक आईबी, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अनेक सरकारी संगठनों के अधिकारी, विभिन्न बैंकों/वित्तीय मध्यस्थों, फिनटेक, मीडिया, साइबर कमांडो, NCC और NSS कैडेट शामिल होंगे।

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर Safe Cyber Space अभियान के तहत 2015 में I4C की स्थापना हुई थी, तब से यह लगातार एक साइबर सुरक्षित भारत का मजबूत स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 से 2024 की 9 साल की यात्रा में ये विचार एक इनीशिएटिव और फिर एक इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है और आज सभी नई पहलों में तकनीक का बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग से कई खतरे भी पैदा हो रहे हैं और इसीलिए साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू भी बन गई है। श्री शाह ने कहा कि I4C जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रकार के खतरों से निपटने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। उन्होंने I4C से सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझा प्रयास को जारी रखने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी एक संस्था अकेले साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं रख सकती। यह तभी संभव है जब कई स्टेकहोल्डर्स एक ही मंच पर आकर एक ही तरीके और रास्ते पर आगे बढ़ें।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां I4C के चार प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना थी, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ आज साइबर कमांडो, समन्वय प्लेटफॉर्म और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का भी शुभारंभ हुआ है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य के पास साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री अलग-अलग रहने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि राज्यों की अपनी सीमा है लेकिन साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए और राज्यों को इसके साथ जोड़कर साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाए। इस पहल से आने वाले दिनों में साइबर अपराधों की रोकथाम में हमें बहुत मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज से I4C एक जनजागरूकता अभियान भी शुरू कर रहा है। देश के 72 से अधिक टीवी चैनल्स, 190 रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को गति देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित को साइबर अपराध से बचने का तरीका नहीं पता होगा तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा किसाइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और I4C के अन्य प्लेटफॉर्म्स के बारे में जागरूकता फैलाने से इसकी उपयोगिता बढ़ेगी और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान से जुड़कर गांवों और शहरों तक जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (सीएफएमसी)के साथ बैंक, वित्तीय संस्थान, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस को एक ही मंच पर लाकर इस केन्द्र का विचार रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में यह साइबर अपराध की रोकथाम का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनेगा। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र को अलग-अलग डेटा का AI के उपयोग से साइबर अपराधियों के काम करने के तरीकों (MO)की पहचान कर इसकी रोकथाम का काम करना चाहिए।श्री शाह ने कहा कि साइबर कमांडो कार्यक्रम के तहत 5 साल में लगभग 5 हज़ार साइबर कमांडो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि need to know के स्थान पर duty to share आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से अधिक कारगर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि data-driven approach के साथ समन्वय प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया गया है और देश में एक साझा डेटा कोष बनाने का यह पहला प्रयास है। गृह मंत्री ने कहा कि आज शुरू हुए चार इनीशिएटिव I4C और देशभर की पुलिस ने साथ में मिलकर लिए हैं, ये साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को और पुख्ता, मजबूत और सफल बनाने में बड़ा योगदान देंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को 25 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। उन्होंने कहा कि डाउनलोड स्पीड बढ़ने और लागत कम होने से डेटा की खपत में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले औसत उपयोग 0.26 GB था जो लगभग 78 गुना बढ़ोतरी के साथ आज 20.27GB हो गया है। श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया के इनीशिएटिव के कारण देश में कई सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। 35 करोड़ जनधन खाते और 36 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड के साथ 2024 में 20 लाख 64000 करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटल मधयुम सेहुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि जब डिजिटल अकाउंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षा की ज़रूरत भी बहुत अधिक बढ़ जाती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में देश की मात्र 600 पंचायत इंटरनेट से जुड़ी थीं, आज 2,13,000 पंचायत जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन और डिजिटल डेटा का उपयोग बढ़ने से इसे साइबर फ्रॉड से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, महिला और बाल शोषण, फर्जी समाचार और टूल किट, मिस इनफॉरमेशन कैंपेन जैसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और इनसे निपटने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है।

**केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों** - भारतीय

**(शेष पृष्ठ 4 पर)**

# भारत की राष्ट्रपति ने श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह की गरिमा बढ़ाई

**कोल्हापुर।** भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने (2 सितंबर, 2024) महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित वारणानगर में श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह की गरिमा बढ़ाई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में निहित शक्ति का सदुपयोग करने के लिए सहकारिता सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सहकारिता के सिद्धांत संविधान में परिकल्पित न्याय, एकता और भाईचारे की भावना के अनुरूप हैं। जब अलग-अलग वर्गों और विचारधाराओं के लोग सहकार के लिए एकजुट होते हैं, तो उन्हें सामाजिक विविधता का लाभ मिलता है। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे घरेलू ब्रांड ऐसी सहकारी समितियों के ही उदाहरण हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है तो इस सफलता में सहकारी समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। आम तौर पर सभी राज्यों में सहकारी समितियां मुख्य रूप से दूध उत्पादों का उत्पादन और वितरण करती हैं। केवल दूध ही नहीं, सहकारी संस्थाएं उर्वरक, कपास, हथकरघा, आवास (हाउसिंग), खाद्य तेल और चीनी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सहकारी संस्थाओं ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(पृष्ठ 3 का शेष)

लेकिन तेजी से बदलते इस समय में उन्हें खुद को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई सहकारी समितियां पूंजी व संसाधनों की कमी, शासन व प्रबंधन और कम भागीदारी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को सहकारिता से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। युवा, प्रशासन और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को शामिल करके उन संस्थाओं का कायाकल्प कर सकते हैं। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को जैविक खेती, भंडारण क्षमता निर्माण और इको-टूरिज्म (पर्यटन) जैसे नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने की सलाह दीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी उद्यम की सफलता का असली राज उसका आम लोगों के साथ जुड़ाव है। इसे देखते हुए सहकारी समितियों की सफलता के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी सहकारी संस्था किसी व्यक्ति के निजी स्वार्थ और लाभ कमाने का एक साधन न बने, अन्यथा सहकारिता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सहकारी समितियों में किसी के एकाधिकार की जगह वास्तविक सहकार होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं, से शिक्षा के महत्व को समझने, नई तकनीकों को सीखने, दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण को महत्व देने, जरूरतमंदों की सहायता करने और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास विश्व पटल पर भारत को ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे।

# श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन....

न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम –मेंदेश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए सभी कानूनी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनीशिएटिव के माध्यम से इन्हें कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया है। इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक बनाने और क्वालिटी आफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक प्रकार के नए-नए फ्रॉड में छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल होने लगे हैं। श्री शाह ने कहा कि हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए जल्दी ही विस्तार भी करना होगा और अपराधों का बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण और उसके आधार पर रोकथाम की प्रक्रिया के बारे में निरंतर सोच कर आगे भी बढ़ना होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि I4C ने 9 साल की अपनी यात्रा और गृह मंत्रालय का अधिकृत हिस्सा बनने के बाद एक साल के छोटे से कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है। I4C की सबसे बड़ी उपलब्धि 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने कहा कि इसे पॉपुलर करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर्स की है।गृह मंत्री ने 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर करने के लिए एक जागरूकता पखवाड़ा आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें और गृह मंत्रालय इनीशिएटिव लेकर मिलकर 6 महीने बाद एक जागरूकता पखवाड़ा आयोजित करें।श्री शाह ने कहा कि सभी प्लेटफार्म्स पर एक साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 को पॉपुलर करने का एक अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से फ्रॉड के शिकार लोगों सुरक्षित महसूस करेंगे, तुरंत इसकी रोकथाम होगी और फ्रॉड करने वालों के मन में भी भय उत्पन्न होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि अब तक I4C ने 600 से अधिक एडवाइजरी जारी की हैं, साइबर अपराधियों द्वारा संचालित कई प्रकार की वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पेज, मोबाइल एप्स और अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। उन्होंने कहा कि I4C के तहत दिल्ली में एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।अब तक 1100 से अधिक अधिकारियों को साइबर फॉरेंसिक में प्रशिक्षित किया गया है और इस अभियान को जिलों और तहसील तक ले जाने का हमारा बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में सात ज्वाइंट साइबर कोआर्डिनेशन टीम्स गठित की गई हैं और इनके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। उन्होंने कहा कि I4C ने cyberdost के नाम से विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रभावी जागरूकता अभियान भी चलाया है। श्री शाह ने कहा कि इन सभी प्रयासों से हम एक मुकाम पर जरूर पहुंचे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य अभी काफी दूर है।उन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सटीक तरीके से रणनीति बनाकर और उस पर एकसाथ, एक ही दिशा में आगे बढ़ना होगा।

साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC): साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना नई दिल्ली स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) में की गई है, जिसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी हितधारक ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। सीएफएमसी कानून प्रवर्तन में "सहकारी संघवाद" का एक उदाहरण पेश करेगा।

**समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) :** यह प्लेटफॉर्म एक वेब-आधारित मॉड्यूल है जो साइबर अपराध के डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण, सहयोग और देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समन्वय मंच के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।

**'साइबर कमांडो' कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और CPOs में प्रशिक्षित 'साइबर कमांडो' की एक विशेष शाखा स्थापित की जाएगी। प्रशिक्षित साइबर कमांडो डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करेंगे। **Suspect Registry:** इस पहल के हिस्से के रूप में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई जा रही है।

## शासकीय योजनाओं का लाभ पाने के लिये अब ई-केवायसी सत्यापित समग्र आईडी अनिवार्य

भोपाल : राज्य शासन के प्राय: सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की हितग्राहीमूलक/ समूहमूलक योजनायें एवं नागरिक सेवायें चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पाने के लिये आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराना होता है। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं/सेवाओं के पंजीयन में संबंधितों की ई-केवायसी सत्यापित समग्र आईडी ही मान्य की जायेगी। यह प्रावधान सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस आशय के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

नये दिशा-निर्देशों में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में E-KYC/आधार सत्यापित समय आईडी' का उपयोग करने एवं समग्र API से डाटा पाने के लिये संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करें। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (MPSEDC) की तकनीकी टीम द्वारा समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में समुचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता दी जायेगी। पंजीयन फार्म अथवा नामांकन का डेटा एवं फील्ड में ऐसी जानकारी, जो आधार e-KYC सत्यापित समग्र आईडी से प्राप्त हो सकती है, इसके लिए MPSEDC के साथ API के माध्यम से integrate कर डेटा ले लिया जाये। अन्य माध्यमों से ली जा रही आधार e-KYC सत्यापित सेवाओं के स्थान पर समग्र पोर्टल ( https://www.samagra.gov.in/ ) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही e- KYC सेवा का ही उपयोग किया जाये। ऐसी विभागीय योजनाएं/सेवाएं, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नही हैं, उनके लिए विभागों द्वारा चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल / वेब ऐप्लिकेशन विकसित करने का कार्य आरंभ किया जाये। सभी विभाग हितग्राहियों का समग्र आईडी पर e-KYC सत्यापन कराने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित करें।

# अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजन होगा

**अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 130 वर्षों में पहली बार भारत में अपनी आम सभा और वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है**

**सम्मेलन का विषय है "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है", जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना 'सहकार से समृद्धि' के अनुरूप है**

**यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी करेगा**

**सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा**

**प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन से भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी**

**भारत में सहकारी समितियों की संख्या और सदस्यों की संख्या दोनों ही दृष्टि से वैश्विक संख्या का एक-चौथाई हिस्सा है: डॉ. आशीष कुमार भूटानी**

**भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैक्स मॉडल उपनियमों का क्रियान्वयन था: डॉ. भूटानी**

**सहकारिता सचिव ने कहा कि "सहकार से समृद्धि" का विचार अब पूरी दुनिया में फैलेगा**

**पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, तीन नई सहकारी समितियां, एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल के गठन ने भारत को वैश्विक सहकारिता आंदोलन में अग्रणी स्थान दिलाया है**

**भारतीय सहकारिता आंदोलन हमेशा से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरित रहा है और भारतीय सहकारिता आंदोलन की इस विरासत को जारी रखते हुए, यह आयोजन कार्बन न्यूट्रल होगा**

**इफको की सहायक कंपनी IFFDC पिछले कुछ वर्षों में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक रही है**

**संभावित कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए इफको दस हजार पीपल के पौधे लगाएगा**

**नई दिल्ली।** अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के 130 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, ICA के महानिदेशक श्री हेरोन डगलस और इफको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. यू.एस. अवस्थी द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कार्यक्रमों का विवरण दिया गया।

इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है "Cooperatives Build Prosperity for All", जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण 'सहकार से समृद्धि' के अनुरूप है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा। इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट' में भारतीय सहकारिता के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत में सहकारिता के आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारी समितियों के वैश्विक संख्या का एक-चौथाई हिस्सा भारत में है, चाहे, सदस्यों की दृष्टि से या समितियों की संख्या की दृष्टि से हो। उन्होंने बताया कि भारतीय सहकारी क्षेत्र ने सहकारी आंदोलन के विकास और वृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय की 54 नई पहलों के शुभारंभ के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान प्राप्त करते हुए नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। डॉ. भूटानी ने कहा कि भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैक्स मॉडल उपनियमों का कार्यान्वयन था । डॉ. भूटानी ने कहा कि चाहे वह पैक्स का कम्प्यूटरीकरण हो या सहकारिता क्षेत्र में तीन नई सहकारी समितियों का गठन, जैसे राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCOL), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) या अन्य पहल, इन सबने भारत को वैश्विक सहकारिता आंदोलन में सबसे आगे रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। डॉ. भूटानी ने कहा कि नई दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन से "सहकार से समृद्धि" का विचार अब पूरे विश्व में फैलेगा।

ICA के महानिदेशक श्री हेरोन डगलस ने आयोजित होने जा रहे सम्मेलन के भारत में होने के महत्व पर जोर देकर कहा कि भारत ICA का संस्थापक सदस्य रहा है। सहकारिता मंत्रालय और इफको तथा अन्य सहकारी समितियों की भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री डगलस ने कहा कि भारत वैश्विक सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इफको को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया, जिसकी रैंकिंग लगातार तीन वर्षों से विश्व सहकारी मॉनिटर में नंबर 1 है। श्री डगलस ने कहा कि दुनिया में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि scalability of sustainability के संदर्भ में, सहकारी आंदोलन सभी में सबसे अधिक sustainable और टिकाऊ मॉडल साबित होता है। 200 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड में इसने मानवता के आठवें हिस्से से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है और वर्तमान में देश में सहकारी समितियों की संख्या और उनके विस्तार की संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। श्री हेरोन डगलस ने कहा कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां दुनिया का संकटों की एक श्रृंखला से सामना हो सकता है। जलवायु संकट, जैव विविधता संकट और कई अन्य। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मॉडल के माध्यम से हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के सिद्धांतों के माध्यम से, लोकतांत्रिक रूप से उद्यमों को अपने सदस्यों के बीच उचित मूल्य वितरण के साथ, लिंग, जातीयता, देश, उम्र की परवाह किए बिना हर भागीदार के लिए खुलापन, और सहकारी समितियों के बीच सहयोग की मूल्य प्रणाली, समुदायों का ख्याल रखते हुए, दुनिया अपनी मौजूदा समस्याओं का समाधान पा सकती है।

इफको लिमिटेड के एमडी डॉ. यू.एस. अवस्थी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इफको की सहायक कंपनी IFFDC पिछले वर्षों में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाले अग्रणी फर्मों में से एक रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सहकारिता आंदोलन हमेशा से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरित रहा है और भारतीय सहकारिता आंदोलन की इसी विरासत को जारी रखते हुए यह आयोजन कार्बन न्यूट्रल होगा। डॉ. अवस्थी ने कहा कि संभावित कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए दस हजार पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने पीपल के वृक्षारोपण की संख्या बढ़ाने में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. अवस्थी ने बताया कि कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए लगभग 4000 पेड़ लगाने की जरूरत है, लेकिन सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी की भलाई के लिए 10,000 पेड़ लगाने पर जोर दिया और वह भी पीपल के पेड़ जो अच्छे कार्बन अवशोषक हैं।

इस कार्यक्रम में भूटान के माननीय प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद (यूएन ईसीओएसओसी) के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, आईसीए सदस्य, भारतीय सहकारी आंदोलन के प्रमुख तथा 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 प्रतिष्ठित अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

# "सहकारी क्षेत्र का विकास : आत्मनिर्भरता के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का सशक्तिकरण" विषय पर नई दिल्ली में एक व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किया

**प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय जनवरी 2025 तक देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेगा**

**केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के भीतर 2 लाख नए PACS को डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक पंचायत में व्यवहार्य (Viable) सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है**

**केन्द्रीय सहकारिता सचिव डॉ. भूटानी ने सभी मक्का किसानों से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत NCCF और NAFED द्वारा खरीद के लिए Farmers 'पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की अपील की, यह किसानों और इथेनॉल मिश्रण मिशन दोनों के लिए फायदेमंद होगा**

**देश भर में 31 हजार से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ERP सॉफ्टवेयर पर आईं, 21 हजार से अधिक PACS लाइव हुए**

**केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मक्का और दाल उत्पादक पूर्व पंजीकृत किसानों की पूरी उपज MSP पर खरीदी जाएगी**

**नई दिल्ली।** केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय ने "सहकारी क्षेत्र का विकास: आत्मनिर्भरता के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का सशक्तिकरण" विषय पर आज नई दिल्ली में एक व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किया, जिसमें देश में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) सहित विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों सहित देश भर के हितधारक मौजूद थे। साथ ही, देश भर से 200 से अधिक अन्य हितधारकों ने वर्चुअल माध्यम से परामर्श सत्रों में भाग लिया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप, मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक या जनवरी 2025 तक देश में सभी PACS के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। उन्होंने कहा कि 2 लाख नए बहुउद्देश्यीय PACS बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि देश के उन इलाकों को कवर किया जा सके जिन्हें अब तक कम या बिल्कुल भी नहीं कवर किया जा सका है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के भीतर 2 लाख नए PACS को डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक पंचायत में व्यवहार्य (Viable) सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है।

केन्द्रीय सहकारिता सचिव डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के वादे के अनुसार मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्का खरीद के लिए तैयार है। उन्होंने सभी मक्का किसानों से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) द्वारा खरीद के लिए किसान पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह किसानों और इथेनॉल मिश्रण मिशन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के संशोधित लक्ष्य की घोषणा की और इसे प्राप्त करने की पूर्व समयसीमा को 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया।

PACS के डिजिटलीकरण पर हुई चर्चा में सभी व्यवहार्य PACS को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) आधारित सॉफ्टवेयर पर लाने, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से NABARD के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। अब तक इस परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 67,930 PACS को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रु. 654.23 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है। परियोजना के तहत NABARD को रु.141 करोड़ भी जारी किए गए हैं। 30 अगस्त 2024 तक, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 31,301 PACS को ERP सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है और 21,477 PACS लाइव हो गए हैं।

PACS को व्यवहार्य व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों से लेकर पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और बीजों के वितरण तक के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में किसानों को मक्का और दालों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करके PACS को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मक्का और दालों का उत्पादन करने वाले पहले से पंजीकृत किसानों की पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है।

परामर्श सत्र का समापन उन रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ हुआ, जिन पर आज चर्चा की गई। सत्र के दौरान PACS को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर संस्थाएँ बनने में सहायता करने के लिए हितधारकों ने मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

परामर्श सत्र में NABARD, गुजरात राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ (NAFSCOB), करीमनगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बनासकांठा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सहित कई अन्य सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

## मछुआ सहकारी समितियो एवं मछुआ समूह

**राजगढ़ :** कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग विभाग श्री भारत सिंह मीणा द्वारा मछुआ सहकारी समितियो एवं मछुआ समूह अंतर्गत ग्राम भूतियाबे जलाशय में 13 हेक्टेयर, माँ लालबाई माता मछुआ सहकारी समिति माचलपुरग्राम बिलोड़ा जलाशय 23.24 हेक्टयर,ग्राम गोघड़पुर जलाशय में 50.22 हेक्टयर, ग्राम खारखेड़ा जलाशय में 19.245 हेक्टयर,ग्राम डोव जलाशय 68 हेक्टेयर, ग्राम पिपलिया बिजरोल 49.38 हेक्टेयर तथा ग्राम शंकरपुरजलाशय 35.508 हेक्टेयर जलाशयों को 10 वर्ष के लिए मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिए गए है। प्रदेश सरकार की मंशानुसार प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग श्री नारायण सिंह पंवार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सहित ज़िले के मछुआ सहकारी समितियो एवं मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की समीक्षा

## प्रबंधकों के पास शाखाओं की सामान्य जानकारी नहीं होने पर

**राजगढ़ :** कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने गुरूवार को आयोजित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की बैठक शाखा प्रबंधकों को शाखाओं से संबंधित जानकारी नहीं होने के कारण बैठक स्थगित की। उन्होंने कहा कि शाखा प्रबंधकों की इस तरह की लचर कार्यप्रणाली से ही बैंक की स्थिति कमजोर हो रही है।

कलेक्टर ने बैठक की शुरूआत में राजगढ एवं ब्यावरा के शाखा प्रबंधकों से उनकी शाखाओं में सक्रिय एवं निष्क्रिय खातों तथा खातों की ई-केवायसी की जानकारी पूंछी,जो यह शाखा प्रबंधक संतोष जनक तरीके से नहीं बता पाए। कलेक्टर द्वारा बैठक में तैयारी से नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं राजगढ के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने एवं खातों की ई-केवायसी करने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जाए।

इस दौरान उपायुक्त सहकारिता श्री नरेश सिन्हा एवं बैंक के सीईओ श्री पी.एन. यादव भी मौजूद थे।

# समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के पंजीयन 19 से होंगे प्रारम्भ

## जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्टर ने तैयारियों के दिये निर्देश

कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने गत दिवस बुधवार देर शाम को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सम्बंध में जिला उपार्जन समिति की बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से किसानों के पंजीयन केंद्रों को बढ़ाने के निर्देश दिए है। 19 सितम्बर से प्रारम्भ हो रहें पंजीयन के लिए खासकर ऐसे स्थल जहां कियोस्क सेंटर व कॉमन सर्विस सेंटर्स की कमी है। वहां पंजीयन केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए है। साथ ही उपार्जन से जुड़े अमले के प्रशिक्षण के संबंध में निर्देशित किया गया। उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का सत्यापन का कार्य राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाएगी। बैठक में सीसीबी के सीईओ श्री आरसी पटले, कृषि उपसंचालक श्री राजेश खोब्रागड़े, खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल,नागरिक आपूर्ति, मार्केटिंग व एनआरएलएम की पीओ भी मौजूद रही।

## धान उपार्जन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अनुभाग स्तरीय समिति गठित

**जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसान पंजीयन एवं समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अनुभाग स्तरीय उपार्जन समिति का गठन किया गया है।**

**बालाघाट :** जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसान पंजीयन एवं समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अनुभाग स्तरीय उपार्जन समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशन में गठित इस समिति की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा की सुनिश्चित जाएगी। वहीं समस्याओं के निराकरण एवं पर्यवेक्षण के दौरान अनुभागों के एसडीएम के साथ ही अन्य सदस्यों में तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, एमपीएससीएससी के शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक एमपीडब्लूएलसी एवं सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

# सहकारी समितियों के संस्था प्रबंधकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

**खरगोन :** सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के सभाकक्ष में सहकारी समितियों के संस्था प्रबंधकों का एन.पी.ए. प्रबंधन विषय पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का डी.डी.एम. नाबार्ड विजेन्द्र पाटील के मुख्य आतिथ्य दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यकम नाबार्ड (सॉफ्टकाब) योजना अन्तर्गत सहकारी प्रबधं संस्थान भोपाल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन के एम.डी. पीएस धनवाल द्वारा कहा गया कि पैक्स की वित्तीय स्थिति को उनके एनपीए ऋण सीधे-सीधे प्रभावित करते है। संस्थाओं के द्वारा प्रदाय ऋण एन.पी.ए. होने से संस्थाओं के लाभार्जन में कमी होती है, उनके द्वारा एन.पी.ए. की कमी हेतु संस्था द्वारा प्रदाय किये गये ऋणों की वसूली पर विस्तृत विचार व्यक्त किये तथा अपेक्षा की गयी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित प्रतिभागी पूर्ण गंभीरता से सहभागिता करें।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये विजेन्द्र पाटील जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड द्वारा बताया गया कि बी-पैक्स दशकों से कृषकों के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र में महत्वूपर्ण भुमिका निमा रहे है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के द्वारा सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाता है तथा इस प्रकार की कार्यशालाएँ संस्थागत विकास के तौर पर की जा रही है, जिसके माध्यम से संस्थाओं का किस प्रकार वित्तीय विकास हो इस पर तथा मानव संसाधन के विकास पर उन्होंने विचार व्यक्त किये।

कार्यशाला में सहकारी प्रबंध संस्था भोपाल से पी. के. परिहार कार्यकम समन्वयक द्वारा बताया कि यह 03 दिवसीय प्रशिक्षण है जिसमें मुख्य रूप से वसूली कार्य योजना, एन.पी.ए. प्रबंधन, वसूली में निरोधक एवं उपचारात्मक विषयों के साथ-साथ पैक्स वित्तीय स्वास्थ एवं लाभप्रदता पर एन.पी.ए. का प्रभाव एवं एन.पी.ए. की गणना पर विशेष फोकस किया जावेगा।

कार्यक्रम में बैंक अधिकारी अनिल कानुनगो, राजेन्द्र आचार्य, श्रीमती संध्या रोकड़े सहित खरगोन बडवानी जिले की बी-पैक्स के 35 संस्था प्रबंधक उपस्थित थे कार्यकम का संचालन अपिल कानुनगो प्रबंधक स्थापना द्वारा किया गया।

# ड्रोन दीदी बनकर महिला कृषक भर रही सपनों की उड़ान

**डिण्डोरी :** जिले में आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। चूंकि वर्तमान में तकनीकी का प्रवेश हर क्षेत्र में है एवं कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी को अपनाया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने एवं खेती में बेहतर योगदान सुनिश्चित करने हेतु की गई है। जिससे महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हो रहीं हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता एवं दक्षता में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

नमो ड्रोन दीदी योजना अन्तर्गत विगत दिवस विकासखण्ड अमरपुर के ग्राम भैंसवाही के कृषक श्री राजेन्द्र साण्डया एवं ग्राम साम्हर के कृषक श्री रतनसिंह के खेत में ड्रोन के माध्यम से रामतिल में अमरबेल के नियंत्रण हेतु पेन्डीमैथेलीन शाकनाशी का छिडकाव किया गया। ड्रोन का संचालन ड्रोन दीदी श्रीमति कमला यादव ग्राम अलौनी के द्वारा किया गया। इन्होंने ड्रोन प्रशिक्षण दिल्ली एवं भोपाल से प्राप्त किया है। ड्रोन के माध्यम से प्रति एकड़ 7 मिनिट में छिड़काव किया जा सकता है, जबकि स्प्रेयर से छिडकाव करने में एक घण्टे से अधिक समय लगता है। ड्रोन से छिड़काव करने में समय एवं श्रम लागत की बचत होती है। ड्रोन द्वारा छिडकाव के समय वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ० पी.एल. अम्बुलकर कृषि विज्ञान केन्द्र डिण्डौरी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी डिण्डौरी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अमरपुर, कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषकगण उपस्थित रहे।

# बीज संघ की संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न

भोपाल। बीज संघ के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 3/9/2024 को मंत्रालय वल्लभ भवन में माननीय श्री विश्वास सारंग,सहकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष बीज संघ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त,अपर मुख्य सचिव सहकारिता, सचिव किसान कल्याण कृषि विकास, पंजीयक सहकारी संस्थाएं सहित अन्य संचालक सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में 6 बीज सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की गई तथा 19 वी वार्षिक साधारण सभा के विषयों का अनुमोदन किया गया। बैठक के विषयों का प्रस्तुतीकरण, बीज संघ प्रबंध संचालक ए के सिंह द्वारा किया गया।

## प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लाभांश का चेक दिया

**भोपाल।** माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 03.9.2024 को सहकारिता विभाग की समीक्षा की गयी, जिसमें अपेक्स बैंक अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपेक्स बैंक में राज्य शासन द्वारा रूपये 142 करोड़ की अंशपूंजी निवेशित की है। अपेक्स बैंक को प्रशासक श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव के द्वारा अपेक्स बैंक की दिनांक 23.8.2024 को आयोजित आमसभा में अंशधारियों को 3 प्रतिशत लाभांश दिये जाने की घोषणा की गयी थी, जिसके तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य शासन के पक्ष में घोषित लाभांश की राशि रूपये 4 करोड़ 27 लाख का चेक अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक द्वारा सौंपा गया। अपेक्स बैंक द्वारा विगत 4 वर्षो में अब तक कुल राशि रूपये 12 करो 10 लाख का लाभांश राज्य शासन को दिया।

## मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

ई-8/77, शाहपुरा भोपाल-462039

### वार्षिक साधारण सभा की सूचना

समस्त सदस्य, सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 25.03.1958) की 53 वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 26 सितम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्थान राज्य संघ कार्यालय, ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है। गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे हेतु स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

**टीप:-** 1. सभी सदरस्यों को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। अप्राप्ति की स्थिति में इस विज्ञापन को ही सूचना जाना जावे।

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध
प्रवेश
पहले आयें प्रवेश पायें
PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 12000/-(6000 प्रति सेमेस्टर)
DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 10000/- (5000 प्रति सेमेस्टर)
संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल
फोन:0755-2926160, 2926159 मो. 9893281971, 8770988938
Website-www.mpscu.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन-452006 - मो. 913139234, 8109186990, 7974058199
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।